मई, 2023, वर्ष : 44 अंक : 05

www.indiatibet.net

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

भारत तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती समारोह में परम पावन दलाई लामा।

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

तिब्बत देश

मई, 2023, वर्ष : 44 अंक : 05

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन, ताशी देकि

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग।

समाचार -

• परम पावन ने जी- ७ नेताओं के 'परमाणु हथियार मुक्त दुनिया' के आह्वान का स्वागत किया 1

• भारत- तिब्बत सहयोग मंच के २५ साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन 2

• बीबीसी के 'हार्ड टॉक' शीर्षक वाले विशेष साक्षात्कार के दौरान सिक्योंग ने तिब्बत के भीतर वास्तविक स्वायत्तता की आशा का दावा किया 3

• सर्वदलीय संसदीय दल से मुलाकात के साथ सिक्योंग की नॉर्वे यात्रा संपन्न 4

• सिक्योंग डेनमार्क के सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, थिंक टैंकों और डेनमार्क में पुराने तिब्बत समर्थकों से मिलेंगे 5

• सिक्योंग ने डेनमार्क सरकार से विदेशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमिका बनाए रखने की अपील की 6

• संयुक्त राष्ट्र अधिकार विशेषज्ञ ने तिब्बत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जबरन श्रम पर चिंता जताई स्थिति की तुलना झिंझियांग में उग्यूरों से की जा रही है। 7

• जी- ७ के नेता तिब्बत में मानवाधिकार और जबरन श्रम को लेकर चिंतित 8

• कालोन नोरज़िन डोल्मा मेडेन ने दक्षिणी भारत की यात्रा में तिब्बत में मानवाधिकारों के गिरती स्थिति पर चिंता जताई और कर्नाटक के तिब्बत समर्थक समूहों से मुलाकात की 9

• तिब्बत समर्थक मधु लिमये का जन्म शताब्दी समारोह और डॉ. निर्मला देशपांडे का स्मृति समारोह दिल्ली में आयोजित 10

समाचार -

• भारत-तिब्बत मैत्री संघ ने चीन-तिब्बत संघर्ष समाधान के आह्वान को दोहराया 11

• अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने तिब्बती जन डीएनए संग्रह पर चिंता जताई 12

• दुर्दमनीय तिब्बत: करुणा और सच्चाई के बूते चीनी झूठ से लड़ने के सात दशक 13

• स्विस पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह पर थर्मो फिशर को खुला पत्र भेजा 14

• संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय ने चीन से तिब्बती महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया 15

• सीआरओ जिग्मे सुल्ट्रिम ने तिब्बती नेतृत्व की ओर से कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को बधाई पत्र भेजा 16

• धोंडुप वांगचेन ने परिवार के साथ टोक्यो की यात्रा की 17

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत -तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

अपनी बात ◆ # पेंछेन लामा गेंदुन छोकी नीमा को शीघ्र रिहा करे चीन

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु परमश्रद्धेय दसवें पेंछेन लामा के अवतार गेंदुन छोकी नीमा की शीघ्र रिहाई हेतु विष्वस्तरीय अपील से चीन सरकार की तानाषाही एवं हठधर्मिता फिर उजागर हो गई है। गेंदुन छोकी नीमा सिर्फ छः वर्ष के थे जब 17 मई, 1995 को चीन सरकार ने उनका सपरिवार अपहरण कर लिया था। उसी समय उनके गुरु थल्रेल रिंपोछे का भी चीन सरकार ने अपहरण कर लिया था। चीन सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण तथा निंदनीय कार्य से पूरा विष्व स्तब्ध था। यह घटना 28 वर्ष पूर्व की है। तब से अब तक गेंदुन छोकी नीमा, उनके गुरु थल्रेल रिंपोछे तथा परिजनों के बारे में चीन सरकार तथ्यों को छिपाती रही है। वह सच्चाई नहीं बताती। यह गंभीर चिंता का विषय है।

बौद्ध परंपरानुसार पेंछेन लामा के अवतार का निष्चय किया जाता है। उसकी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका पालन बौद्ध धर्मगुरुओं तथा विद्वानों द्वारा किया जाता है। यह परंपरा सदियों से जारी है। इसी पारंपरिक प्रक्रिया के अनुरूप 14 मई, 2023 को परमपावन दलाई लामा ने गेंदुन छोकी नीमा को दसवें पेंछेन लामा का अवतार घोषित किया था।

विस्तारवादी चीन सरकार को दलाई लामा द्वारा घोषित पेंछेन लामा के अवतार गेंदुन छोकी नीमा की सामाजिक स्वीकृति बर्दाष्त नहीं हुई। उसने 14 मई की घोषणा पर 17 मई को ही पानी फेर दिया तथा गेंदुन छोकी नीमा का सपरिवार अपहरण कर लिया। साम्यवादी चीन सरकार धर्म को अफीम बताती है। इसके बावजूद तिब्बत के धार्मिक मामले में उसकी साजिषपूर्ण गहरी रुचि हमेषा रहती है।

चीन सरकार की षड्यंत्रपूर्ण रुचि का ही प्रमाण है कि उसने तिब्बती धर्मगुरु कर्मापा के पद पर अपनी पसंद के एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था। तब परंपरागत तरीके से चुने गये कर्मापा जी को छिपते-छिपाते भारत आना पड़ा। चीन सरकार अभी से दलाई लामा के नये अवतार को चुनने की भी साजिष रच रही है। दलाई लामा के अवतार को चुनने की भी सुव्यवस्थित पारंपरिक प्रक्रिया है। समस्त बौद्ध समुदाय ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। इसी पक्ष में सभी तिब्बत समर्थक तथा बौद्ध समर्थक भी हैं। किसी भी तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु को चुनने का अधिकार साम्यवादी चीन सरकार को नहीं है। तिब्बत के धार्मिक मामले में उसके अवांछित हस्तक्षेप का भरपूर विरोध किया जायेगा।

इस समय निर्वासित तिब्बत सरकार, जो कि तिब्बती समुदाय द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से मतदान के जरिये निर्वाचित की गई है, की मांग है कि चीन सरकार यथाशीघ्र पेंछेन लामा को रिहा करे। इसके अन्तरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने विष्व के सभी देषों की सरकारों से इस हेतु चीन सरकार पर दबाव डालने की अपील की है। सभी तिब्बत समर्थकों ने भी पेंछेन लामा के अपहरण की 28वीं वर्षगाँठ पर आयोजित कार्यक्रमों में चीन सरकार से यही अपील की है। उन्होंने सभी देषों के जनप्रतिनिधियों तथा लोकतांत्रिक संगठनों से इस विषय में भरपूर सहयोग एवं समर्थन का आह्वान किया है।

तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। गत 5 मई, 2023 को अपने रजत जयंती समारोह में भारत-तिब्बत सहयोग मंच द्वारा इसे प्रामाणिकता के साथ उठाया गया। हिमाचल प्रदेष के कांगड़ा जिलांतर्गत धर्मषाला में सहयोग मंच की स्थापना हुई थी। रजत जयंती समारोह भी इसी धर्मषाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार सुगलाखांग के परिसर में हुआ। परमपावन दलाई लामा समारोह के मुख्य अतिथि थे। सहयोग मंच के संस्थापक माननीय इन्द्रेष कुमार समेत कई गणमान्य विचारक इसमें शामिल थे। दलाई लामा ने अपने संबोधन में तिब्बतियों को भरपूर सहयोग एवं समर्थन देते रहने के लिये भारत सरकार, भारतीय जनता तथा अन्य सभी समर्थक संगठनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने भारत-तिब्बत सहयोग मंच के कार्यों की प्रसन्नतापूर्ण प्रषंसा करते हुए विष्वास व्यक्त किया कि भारत और तिब्बत के बीच गुरु-षिष्य संबंध और मजबूत होता रहेगा।

चीन सरकार तिब्बत में एक “आत्मसात नीति” चला रही है। इससे तिब्बती बच्चे अपनी तिब्बती संस्कृति, भाषा, इतिहास एवं गौरव को आत्मसात नहीं करके चीनीकरण का षिकार हो रहे हैं। तिब्बत के लिए ऐसी विनाषकारी नीति। तिब्बती पहचान को मिटाने का यह चीनी षड्यंत्र है। चीन सरकार द्वारा तिब्बत में संचालित “कोलोनियल बोर्डिंग स्कूल” भी इसी प्रकार के चीनी हथकंडे हैं। तिब्बती बच्चे अपने माँ-बाप एवं अन्य परिजनों से दूर इन स्कूलों में बौद्ध दर्षन की जगह साम्यवादी दर्षन से भरपूर वातावरण में रखे जाते हैं। वहाँ उन्हें सुनियोजित तरीके से तिब्बती संस्कारों से अलग कर दिया जाता है। वे चीन सरकार की योजना के अनुरूप चीनीकरण के षिकार हो रहे हैं। इस प्रकार तिब्बत का चीनीकरण करने में तिब्बती बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरह ही अन्य तिब्बत समर्थक संगठन एवं विचारक भी तिब्बत की बिगड़ती ऐसी आंतरिक दषा से चिंतित हैं।

संपूर्ण विष्व, विषेषकर एषिया और उसमें भी हिमालय क्षेत्र तथा भारत के हित में तिब्बत समस्या का समाधान जरूरी है। भारत-तिब्बत वार्ता पुनः प्रारम्भ होने हेतु उपयुक्त वातावरण बने। इसके लिये चीन सरकार पर दबाव बढ़ाने का यह उचित समय है। विष्व जनमत तिब्बतियों के पक्ष में है। विस्तारवादी चीन सरकार पर नियंत्रण संपूर्ण संसार के हित में है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ परम पावन ने जी- ७ नेताओं के 'परमाणु हथियार मुक्ति दुनिया' के आह्वान का स्वागत किया

dalailama.com / २३ मई, २०२३

मैं जापान के हिरोशिमा में हाल में ही आयोजित जी-७ नेताओं के शिखर सम्मेलन में दिए गए 'परमाणु हथियार मुक्त दुनिया' के आह्वान संबंधी संयुक्त बयान का तहेदिल से स्वागत करता हूं। यह संयुक्त बयान दुनिया की इस वास्तविकता को दर्शाता है कि हम दिनानुदिन एक- दूसरे पर निर्भर होती जा रही दुनिया में रह रहे हैं और इस २१वीं सदी को शांति और सहयोग की सदी बनाने की ओर अग्रसर हैं।

मैं दुनिया को विसैन्यीकरण करने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने का अभियान चला रहा हूं। ऐसे में मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह एक सकारात्मक पहल है। जनवरी- २०२२ में भी मैंने पांच परमाणु-हथियार संपन्न देशों के उस संयुक्त प्रतिज्ञा की गर्मजोशी से सराहना की थी कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा ही जाना चाहिए।

दुनिया के कई हिस्सों में अनिश्चितता और उथल-पुथल के इस दौर में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए गंभीर और ठोस प्रयास करें। इसलिए जी- ७ देशों की प्रतिबद्धताएं शक्तिशाली संदेश देती हैं और इन हथियारों से मानवता पर मंडराने वाले खतरे को समाप्त करने की महतता को मान्यता देती हैं।

परमाणु हथियारों के बिना दुनिया संभव है और यह जरूरी भी है। हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में हिंसा उन लोगों को भी संकट और कष्ट में डाल देती है, जो संघर्ष से दूर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी मानवता की एकता को याद रखेंगे और यह याद रख सकते हैं कि किसी के भी खिलाफ हिंसा, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है, हम सभी को नुकसान पहुंचाता है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि यह २१वीं सदी अधिक करुणाशील, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विश्व बने।

◆ भारत- तिब्बत सहयोग मंच के २५ साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन

dalailama.com, ०५ मई, २०२३

थेगछेन छोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। परम पावन दलाई लामा ०५ मई की सुबह अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों में से एक- भारत- तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) की स्थापना की २५वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छुगलगखांग मंदिर के प्रांगण में आयोजित सभा में शामिल हुए। संस्था के मुख्य संरक्षक डॉ. इंद्रेश कुमार ने परम पावन के आवास के द्वार पर ही उनका स्वागत किया और फिर कुछ देर खड़े रहे। इस दौरान परम पावन के साथ मंच के सदस्यों की तस्वीरें ली गईं।

भारतीय पद्धति से स्वागत करते हुए परम पावन को फूल और दीप भेंट किया गया और उनके माथे पर तिलक लगाया गया। इसके बाद उनका पारंपरिक तिब्बती पद्धति से स्वागत किया गया, जिसमें 'चेमा चांगपू' शामिल था। इसके बाद परम पावन केंद्रीय गलियारे की ओर बढ़े, जहां पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित तिब्बतियों ने उन्हें काटा यानि सफेद रेशमी स्कार्फ देकर उनका स्वागत किया। वह तिब्बती कला प्रदर्शन संस्थान (टीआईपीए) के ताशी शोल्पा नर्तकियों को देखने के लिए रुके। अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने इस सामरोह का उद्घाटन करने

के लिए सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के उपक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालक कर रहीं बहन ने उपस्थित श्रोताओं को बताया कि वे लोग परम पावन को अपने बीच पाकर कितने धन्य महसूस कर रहे हैं। मुख्य अतिथियों के औपचारिक स्वागत में सभी को पारंपरिक हिमाचली टोपी भेंट की गई। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित अतिथियों के समूह को गेंदे की एक विशाल माला से चारो ओर से घेर दिया गया।

बीटीएसएम के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गोयल ने सबसे पहले 'जय भारत, जय तिब्बत' के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने मुख्य अतिथि व दर्शकों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अपने गठन के बाद से अब तक २५ वर्षों में बीटीएसएम ने पूरे भारत

में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि परम पावन का आशीर्वाद पाकर सदस्य कितने गौरवान्वित हुए हैं और वे तिब्बत के लिए अपना समर्थन बनाए रखने के लिए कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अपनी कई गतिविधियों में बीटीएसएम लोगों को हिमालय की तीर्थयात्रा पर ले जाता है। गोयल ने घोषणा की कि तिब्बत एक दिन फिर से आजाद होगा और भारतीय और तिब्बती कैलाश शिखर पर एक साथ जश्न मनाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल संगठन का प्रमुख लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को इस संगठन का सदस्य बनाना है।

इसके बाद मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने सभा को संबोधित किया और भारत-तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने परम पावन की भूरि- भूरि प्रशंसा की। उन्होंने ध्यान दिलाया कि बुद्ध पूर्णिमा पर सभा का आयोजन कितना शुभ कार्य है और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बुद्धदेव के मंगल उपदेश आज भी हमारे साथ हैं।

अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की पारंपरिक कहानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंततः अहिंसा के माध्यम से अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने पुष्टि की कि बीटीएसएम अपनी गतिविधियों में हमेशा अहिंसक रुख अपनाता है क्योंकि हिंसा का सहारा लेने से केवल मानवता का नुकसान ही होता है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन ने तिब्बत और तिब्बतियों के साथ गलत व्यवहार किया है, उसके लिए चीन को आड़े हाथों लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बीटीएसएम उन सभी तिब्बतियों को याद करते हुए चीन को जवाबदेह ठहराएगा, जो तिब्बत पर उसके कब्जे के कारण पीड़ित हुए हैं। उन्होंने 'ऊं मणि पदमे हुं' मंत्र का जाप किया।

उन्होंने तिब्बत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बीटीएसएम की योजनाओं की ओर इशारा किया और तिब्बती मुद्दे के लिए काम करना जारी रखने का वादा किया। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था और कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने 'जय तिब्बत, जय भारत' के नारे के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।

इसके बाद परम पावन ने अपना संबोधन इस टिप्पणी के साथ प्रारंभ किया कि उनके निर्वासन में आने के बाद पंडित नेहरू ने उनके रहने के लिए यहां धर्मशाला में व्यवस्था की थी।

उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है, एक ऐसी जगह जहां हमें धर्म पालन करने की स्वतंत्रता मिली है। यहां विश्व के सभी धर्मों का पालन करने वालों का सम्मान किया जाता है, पर बौद्ध धर्म का तो जन्म ही इसी देश में हुआ। इसलिए कांग्यूर और तेंग्यूर संग्रहों में शामिल सभी ग्रंथों का शीर्षक 'भारत की भाषा में' शुरू होती हैं। भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से विशेष संबंध रहे हैं और इस तरह से हमारी गहन परंपराएं कायम हैं।

उन्होंने कहा कि सातवीं शताब्दी में तिब्बती राजा छोंगछेन गम्पो ने एक चीनी राजकुमारी से विवाह किया जो तिब्बत और चीन के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों को इंगित करता है। हालांकि, जब लिपि के तौर पर तिब्बती रूप को फिर से डिजाइन करने की बात आई तो राजा ने इसे भारतीय देवनागरी वर्णमाला के आधार पर तिब्बती स्वरों और व्यंजनों को संयोजित करना चुना।

छोंगछेन गम्पो के समय तिब्बत में बहुत से चीनी भिक्षु थे। लेकिन बाद के एक राजा ठिसोंग देछेन ने बौद्ध साधना के चीनी और भारतीय दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करवाने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीय आचार्य कमलशील और चीनी भिक्षुओं के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया। कमलशील ने तीन सर्वोच्च शिक्षाओं आदि की गहन व्याख्या की, जबकि चीनी भिक्षुओं के पास कहने के लिए बहुत-कुछ नहीं था। राजा ने फैसला किया कि अध्ययन, चिंतन और ध्यान के महत्व पर जोर देने वाली कमलशील की पद्धति तिब्बतियों के लिए केवल चीनी ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अधिक उपयुक्त है। इसके बाद उन्होंने चीनी भिक्षुओं को तिब्बत छोड़ने के लिए कह दिया।

कमलशील के गुरु और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य शांतरक्षित को भी इससे पहले तिब्बत में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ही हिम भूमि में कारण और तर्क पर निर्भरता के साथ नालंदा परंपरा की स्थापना की थी। उन्होंने आगे सलाह दी कि चूंकि तिब्बतियों की अपनी लिखित भाषा है, इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए संस्कृत या चीनी पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें उनका तिब्बती में अनुवाद करना चाहिए। इस तरह बुद्ध के प्रवचनों का अनुदित संग्रह-कांग्यूर और बाद के आचार्यों के भाष्य ग्रंथ आदि कृतियों का अनुवाद- तेंग्यूर अस्तित्व में आए। नतीजतन, तिब्बती आज भी नालंदा परंपरा के अनुसार बुद्ध के प्रवचनों की व्याख्या करते हैं।

उन्होंने बताया कि इन दिनों कई बौद्ध देशों के भक्त और छात्र इसलिए हमसे मिलने यहां आते हैं क्योंकि हमने बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं को अंगीकार किया है। अधिक क्या कहना, हम साधना के साथ-साथ अध्ययन भी करते हैं। हम शांति के साथ-साथ विश्लेषणात्मक ध्यान की साधना भी करते हैं और शास्त्रों और ग्रंथों को तर्क और कारण की कसौटी पर रखकर अध्यन करते हैं।

जब हम शास्त्रार्थ, विशेष रूप से तर्क- वितर्क के दौरान पक्ष रखते हैं, उस समय यदि चुनौती देने वाला अपने दावे को सही ठहराने के लिए धर्मग्रंथों की पंक्तियों का उद्धरण देता है, तो दूसरा पक्ष उन उद्धरणों को सही मानने पर सम्मान के तौर पर अपनी टोपी उतार देता है। लेकिन यदि वह यह समझता है कि दिए गए उद्धरण सटीक साबित नहीं हो रहे हैं तो वह अपनी टोपी वापस सिर पर रख लेता है और उद्धरण की उचित व्याख्या बताता है।

परम पावन ने आगे कहा, जब मैं छोटा था, तब मैंने अपनी पढ़ाई 'कलेक्टेड टॉपिक्स' के साथ शुरू की थी। फिर मैं शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें से कई को मैंने कंठस्थ कर लिया था। मैंने अपने शिक्षक के पास बैठकर उन ग्रंथों का अध्ययन किया और वाद-विवाद सहायकों की एक टीम के साथ मैंने जो समझा, उस पर वाद-विवाद किया। आज पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि हमारे बौद्ध शिक्षण केंद्रों के ऐसे विद्वानों के साथ बैठना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

आजकल मैं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का इतना आदी हो गया हूँ कि अन्य धार्मिक विद्वानों या यहां तक कि आधुनिक वैज्ञानिकों से भी मिलने के दौरान मुझे लगता है कि मैं आत्मविश्वास से अपना दृष्टिकोण रख सकता हूं।

एक खोजी विश्लेषण करने में सक्षम होना बहुत मूल्यवान है। हमें जो कुछ कहा जाता है हम उसे आँख बंद करके स्वीकार नहीं करते हैं, हम तर्क की कसौटी पर चीजों के कारण की जांच- परख करते हैं।

जब मैं ल्हासा में गेशे (स्नातक) परीक्षा में बैठा तो तीन महान विहारों- गदेन, सेरा और डेपुंग में शास्त्रार्थ के द्वारा मेरी परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उनके आवरण में मेरा दिल घबरा रहा था। परीक्षा के बाद मैं आराम और विश्लेषणात्मक ध्यान के संयोजन में संलग्न होने में सक्षम हो गया था। इससे मुझे अपना दिमाग बदलने में मदद मिली है।

परम पावन ने समझाया कि कैसे प्रतिदिन जागते ही वे बुद्ध की बोधिचित्त और शून्यता के दृष्टिकोण को लेकर शिक्षाओं के सार का ध्यान करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि भारत में पुनः स्थापित शिक्षा के मठीय केंद्रों में कई हजार भिक्षु और भिक्षुणियां अध्ययन, साधना और ध्यान में लगे हुए हैं। उन्होंने उन भिक्षु और भिक्षुणियां द्वारा किए जा रहे अध्ययन साधना और ध्यान के लिए उनकी भूरि- भूरि प्रशंसा व्यक्त की, क्योंकि उनकी इन साधनाओं से ही बौद्ध शिक्षण संरक्षित है। इसके लिए अध्ययन और साधना के संयोजन की आवश्यकता है। उन्होंने इसे जारी रखने का आग्रह किया।

उन्होंने टिप्पणी की कि वह भिक्षुणियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें गेशेमा (महिला स्नातक) बनाने का श्रेय लेने का दावा कर सकते हैं क्योंकि इसे एक नवाचार के तौर पर उन्होंने शुरू किया है। तिब्बती स्कूलों में भी उन्होंने धर्म के अलावा अलग से दर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की है। जहां कभी धार्मिक गुरु हुआ करते थे वहां अब दर्शनशास्त्र के शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा, यहां निर्वासन में हम केवल अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कांग्यूर और तेंग्यूर को संरक्षित करके और उनमें निहित ग्रंथों का अध्ययन करके हमने वास्तविकता के विचारों और चित्त के विज्ञान को बरकरार रखा है। यह विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में दूसरों के लिए व्यापक लाभ का हो सकता है। हम केंद्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर भारत सरकार के उदार समर्थन और प्रोत्साहन के कारण ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। हमारे स्कूलों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलती है लेकिन वे हमारे मूल्यों और परंपराओं को जीवित रखने में भी सक्षम हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं इस अवसर पर भारत सरकार के साथ ही स्थानीय अधिकारियों को उनकी महान कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।'

उनकी इस बात पर सभागार दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

उन्होंने कहा, 'यह भारत-तिब्बत सहयोग मंच अपनी २५वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके तत्वावधान में पूरे भारत के लोगों ने तिब्बत को अपना समर्थन दिया है। हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कई हलकों से समर्थन मिला है और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी मदद की है।'

अपने निवास पर लौटने से पहले परम पावन ने टीपा के कलाकारों को गाते और नृत्य करते हुए देखा जिसका उद्भव तिब्बत के कोंगपो क्षेत्र में हुआ था। इस नृत्य में पुरुष नर्तक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए चल रहे थे, जबकि स्त्रियाँ बाणों की तरकश लिए चल रही थीं। परम पावन ने तरकश में से एक तीर लिया और शुभता के चिह्न के रूप में उसे अपने सामने हवा में उछाल दिया।

◆ बीबीसी के 'हार्ड टॉक' शीर्षक वाले विशेष साक्षात्कार के दौरान सिक्योंग ने तिब्बत के भीतर वास्तविक स्वायत्तता की आशा का दावा किया

tibet.net. ०३ मई २०२३

धर्मशाला। इंग्लैंड की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ०५ मई २०२३ को २३ मिनट की एक ऑडियो क्लिप में तिब्बत से संबंधित कई मुद्दों पर 'बीबीसी हार्ड टॉक' कार्यक्रम में सारा मोंटेग से बातचीत को जारी किया।

यह पूछे जाने पर कि वह तिब्बत के लिए क्या चाहते हैं, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने उत्तर दिया कि वह 'चीन-तिब्बत संघर्ष को अहिंसक शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए स्थिति की वास्तविकता के आधार पर 'न केवल नाम मात्र का बल्कि संपूर्ण रूप में' वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं। मतलब जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद और स्थायी होना चाहिए।'

चीनी सरकार द्वारा बातचीत शुरू न करने के मुख्य कारण के तौर पर तिब्बती प्रशासन के अलगाववादी होने के दावों को खारिज करते हुए सिक्योंग ने स्पष्ट किया कि 'चीन परम पावन के सामने पूर्व शर्त रखता है कि वह यह कहें कि तिब्बत प्राचीन काल से या अति प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। जबकि सच यह है कि मामला ऐसा नहीं है। तिब्बत तब तक स्वतंत्र रहा जब तक कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए यह वास्तविकता है। फिर भी हम तिब्बत

की स्वतंत्र स्थिति को एक तरफ रख देते हैं लेकिन भविष्य में तिब्बतियों के लाभ के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग करते हैं।'

सिक्योंग ने तिब्बती पहचान और संस्कृति के लिए खतरों के बारे में भी बात की, जिसके बीच उन्होंने उदाहरण के तौर पर औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों के नामांकन की हालिया नीति को उठाया। उन्होंने कहा कि इन बोर्डिंग स्कूलों में आपको चीनी भाषा सिखाई जाती है, यहां तक कि शिक्षा का माध्यम भी मंदारिन है। फिर आपको चीनी इतिहास पढ़ाया जाता है, कम्युनिस्ट चीन का ऐतिहासिक संस्करण आपको सिखाया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा कैसे बनाए रखें।'

सीसीपी द्वारा गरीबी में कमी और विकास के दावों के बारे में सिक्योंग ने तिब्बतियों की उनके आर्थिक हितों से ऊपर की वास्तविक आकांक्षाओं को समझने में चीनी सरकार की विफलता पर जोर दिया।

तिब्बत के अंदर सांस्कृतिक क्षरण की चुनौतियों के खिलाफ तिब्बत की पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए सिक्योंग ने पिछले ६३ वर्षों के निर्वासन में तिब्बती बौद्ध धर्म और पारंपरिक शिक्षा के सफल पुनरुद्धार को दोहराया।

◆ सर्वदलीय संसदीय दल से मुलाकात के साथ सिक्योंग की नॉर्वे यात्रा सम्पन

tibet.net, ०२ मई २०२३

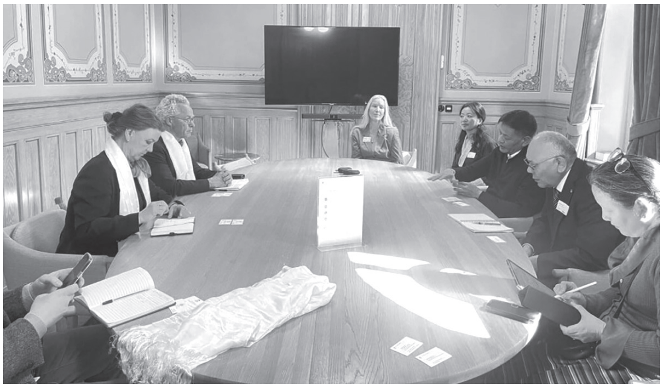

नॉर्वे। वर्तमान में अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में नॉर्वे की यात्रा कर रहे सिक्योंग पेन्पा छेरिंग की मेजबानी नॉर्वे की संसद में की गई, जहां उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मुलाकात की और बातचीत की।

व्यापार और उद्योग पर स्थायी समिति के सदस्य नॉर्वेजियन ग्रीन पार्टी के सांसद रासमस हंससन, विदेश मामलों और रक्षा पर स्थायी समिति के सदस्य और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इंगजर्ड शॉ और लिबरल पार्टी के सांसद तथा ऊर्जा और पर्यावरण विभाग की स्थायी समिति के सदस्य ओला एल्वेस्टुएन के साथ बैठक में सिक्योंग ने सांसदों को तिब्बत के अंदर की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। इसमें चीन सरकार द्वारा संचालित औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों का कार्यान्वयन भी शामिल है। उन्होंने सांसदों को धर्मशाला आने का स्थायी निमंत्रण भी दिया।

बैठक के बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के लिए हवाई अड्डा रवाना होने से पहले सिक्योंग ने यूरोप से तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य और पूर्व प्रतिनिधि चुंगडक कोरेन ला से होटल में मुलाकात की। यूरोप दौरे के तीसरे चरण में डेनमार्क में सिक्योंग सांसदों और थिंक टैंकों, तिब्बत समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे और तिब्बती समुदाय से मिलेंगे।

◆ सिक्योंग डेनमार्क के सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, थिंक टैंकों और डेनमार्क में पुराने तिब्बत समर्थकों से मिलेंगे

tibet.net, ०३ मई २०२३

डेनमार्क। सिक्योंग पेन्पा छेरिंग मंगलवार, ०२ मई २०२३ को डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचे। यह इस देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। सिक्योंग की अगवानी डेमार्क में तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष

तेनपा ग्युर्मे, डेनमार्क की तिब्बत समर्थन समिति के अध्यक्ष एंडर्स एच. एंडरसन, डेनमार्क की डेनिश-तिब्बती सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष ग्रीथे सोरविग के साथ ही डेनमार्क में छात्र और फ्री तिब्बत संगठनों के साथ डेनमार्क में तिब्बती समुदाय के सदस्य टीना और क्लाउडिया ने की।

शाम को उन्होंने १६ वें कशाग द्वारा तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थितियों के आधार पर राजनीतिक समर्थन और तिब्बती मुद्दे पर जुड़ाव और सीटीए के विकास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक समर्थन जुटाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर तिब्बती युवाओं के साथ बातचीत की। सिक्योंग ने युवाओं को अपने समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समुदाय हालांकि छोटा है, लेकिन यह एक शक्तिशाली समूह बन सकता है।

युवाओं के साथ बैठक के बाद सिक्योंग ने डेनमार्क में तिब्बती समुदाय को कई मुद्दों को लेकर संबोधित किया, जिनमें तिब्बतियों की ऐतिहासिक स्वतंत्रता पर आधारित सरकारों और सांसदों के साथ नए सिरे से राजनीतिक जुड़ाव के माध्यम से मध्यम मार्ग नीति के लिए अधिक समर्थन हासिल करने के प्रयास शामिल थे।

आज ०३ मई की सुबह सिक्योंग ने डेनमार्क की संसद में क्रिश्चियनबॉर्ग कैसल, कोपेनहेगन में डेनिश पीपुल्स पार्टी के नेता सांसद मोर्टन मेसर्सच्मिड्ट के साथ बैठक से आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत की।

सिक्योंग के साथ प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी और लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के सचिव लोचो, डेनमार्क स्थित तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष तेनपा ग्युरमे,

एंडर्स होजमार्क एंडरसन और तिब्बत समर्थन समिति डेनमार्क के हाने बेस बोल्सबर्ज थे।
डेनमार्क में प्रवास के दौरान सिक्योंग डेनमार्क की संसद के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, थिंक टैंकों और डेनमार्क में पुराने तिब्बत समर्थकों के साथ मुलाकात करेंगे।

◆ सिक्योंग ने डेनमार्क सरकार से विदेशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमिका बनाए रखने की अपील की

tibet.net, ०६ मई २०२३

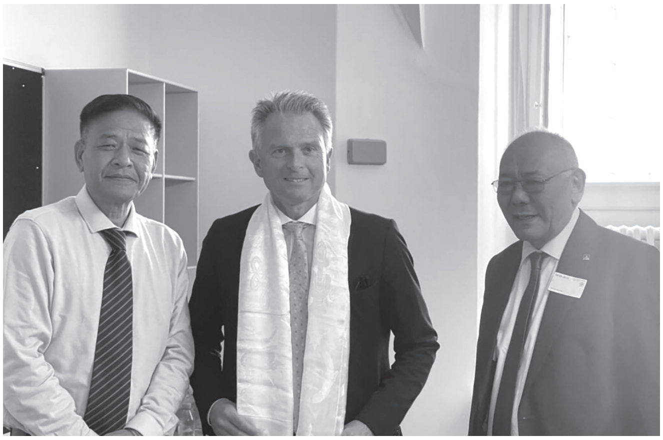

डेनमार्क। डेनमार्क में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग के आधिकारिक कार्यक्रमों के अंतिम दिन डेमोक्रेटिक गैराज (डेमोक्रेसी गैराज) में नॉर्डिक थिंक टैंक फॉर टेक एंड डेमोक्रेसी के अध्यक्ष टोबियास बोर्नाके के साथ बैठक शामिल है। नॉर्डिक देशों में लोकतांत्रिक बहसों पर बड़े तकनीकी प्रभाव को संबोधित करने के लिए डेनमार्क के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित थिंक टैंक में पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के सदस्य शामिल हैं। बैठक में थिंक टैंक के सदस्य भी शामिल हुए। सिक्योंग के साथ प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी, लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के सचिव लोचो समतेन, डेनमार्क स्थित तिब्बत समर्थन समिति के अध्यक्ष एंडर्स हॉजमार्क एंडरसन और उपाध्यक्ष हाने बेस बोल्सबर्जर भी थे।
नॉर्डिक थिंक टैंक फॉर टेक एंड डेमोक्रेसी के साथ बैठक के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने डेनमार्क की संसद की विदेश मामलों और विदेश नीति समिति के सदस्य, संसदीय प्रेसीडियम के तीसरे उपाध्यक्ष और डेनिश संसद में डेनिश सोशलिस्ट पीपुल्स पार्टी के विदेश मामलों के प्रवक्ता सांसद कार्स्टन होंग के साथ मुलाकात की।
दोपहर में सिक्योंग ने डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स का दौरा किया, जहां उन्होंने कोपेनहेगन में संस्थान के कार्यकारी निदेशक लुईस होल्क और अंतरराष्ट्रीय निदेशक मेटे थिगेसन से मुलाकात की। घंटे भर की बैठक में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग और प्रतिनिधियों ने तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति से निदेशकों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ०४ से १८ वर्ष की आयु के दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को चीन सरकार द्वारा संचालित औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों में पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए रखा गया है। इसके अलावा सिक्योंग ने डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे संस्थानों के चीन में काम करने और विदेशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में अपनी सरकार की भूमिका को मजबूती से रखने के महत्व पर जोर दिया।

डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स में अपनी बातचीत के बाद सिक्योंग ने डेनिश संसद में संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्य और डेनिश लिबरल पार्टी के सांसद किम वैलेन्टिन से मुलाकात की।
सिक्योंग पेन्पा छेरिंग की डेनमार्क की पहली आधिकारिक यात्रा डेनिश-चाइना क्रिटिकल सोसाइटी के बोर्ड सदस्यों के साथ एक बैठक के साथ संपन्न हुई। इस दौरान डेनिश युवा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
डेनिश- चाइना क्रिटिकल सोसाइटी एक संगठन है, जिसका उद्देश्य डेनमार्क में चीन के पड़नेवाले दुष्प्रभावों का मुकाबला करना है। संगठन ने ०४ मई २०२३ की शाम कोपेनहेगन में चीन द्वारा मौलिक मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र को लेकर ज्ञान और आलोचना का प्रसार करने के लिए कार्यक्रम किया था।
डेनमार्क में द्विपक्षीय कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक सम्पन हो जाने के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपने आधिकारिक यूरोप दौरे के अंतिम चरण में ०५ मई को जर्मनी के म्यूनिख के लिए उड़ान भरी। म्यूनिख आगमन पर सिक्योंग का स्वागत प्रतिनिधि थिनले चुक्की के साथ तिब्बत ब्यूरो के तेनज़िन छोसांग, जर्मनी में तिब्बती संघ के अध्यक्ष, म्यूनिख में तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष और म्यूनिख- तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने किया।

◆ संयुक्त राष्ट्र अधिकार विशेषज्ञ ने तिब्बत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जबरन श्रम पर चिंता जताई

स्थिति की तुलना झिंझियांग में उग्युरो से की जा रही है।

rfa.org / ताशी वांगचुक, ०१ मई २०२३

संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ ने चिंता जताते हुए कहा है कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण

कार्यक्रमों और श्रमिकों के स्थानांतरण से तिब्बतियों के मानवाधिकारों पर व्यापक दुष्प्रभाव हो सकता है, जैसा कि झिंझियांग में उग्यूरो के साथ हुआ है।

गुलामी के समकालीन रूपों पर संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिपोर्टियर टोमोया ओबोकाटा और संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि तिब्बत में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने और तिब्बतियों की निगरानी और राजनीतिक रूप से उकसाने के लिए किया जा रहा है।

२७ अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में ओबोकाटा और अन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसे कार्यक्रमों से जबरन श्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ के अनुसार, २०१५ के बाद से लाखों तिब्बतियों को उनके पारंपरिक ग्रामीण जीवन से हटाकर अकुशल और कम-वेतन वाले रोजगार में 'स्थानांतरित' कर दिया गया है।

ओबोकाटा ने कहा कि वह चीनी सरकार की प्रतिक्रिया के अनुवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने पहले कहा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी स्वैच्छिक है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रोफेसर ओबोकाटा ने २८ अप्रैल को रेडियो फ्री एशिया को बताया कि, 'लेकिन व्यवहार में और हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्सर उनके (तिब्बतियों) के पास कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है।'

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के सभी मामले जबरन वाले ही हैं, क्योंकि इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन झिंझियांग की तरह की स्थिति में जबरन श्रम के कुछ संकेतक मौजूद मिले हैं, इसलिए हम सरकार से इस स्तर पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और जवाब देने के लिए कह रहे हैं।'

चीनी अधिकारियों द्वारा २०१७ में झिंझियांग में 'पुनः शिक्षा' शिविरों में उग्यूरों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के कुछ मामले आए हैं और कुछ उग्यूरों को जबरन श्रम और अन्य अधिकारों के हनन का शिकार होना पड़ा है। चीनियों का कहना रहा है कि वे शिविर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र थे जो अशांत क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद को रोकने के लिए लगाए गए थे।

अगस्त २०२२ में जारी २० पन्नों की एक रिपोर्ट में ओबोकाटा ने कहा कि झिंझियांग में उग्युर, कजाख और अन्य नस्लीय अल्पसंख्यकों को दो सरकारी प्रणालियों के तहत कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में जबरन श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया जाता है और उग्युर उन्हें कहीं जरूरत के अनुसार काम पर लगा दिया जाता है या अधिशेष ग्रामीण मजदूर के तौर पर रखा जाता है।

ग्रामीण श्रमिकों का स्थानांतरण

रिपोर्ट के अनुसार, इसी तरह के उपाय पड़ोसी तिब्बत में मौजूद हैं, जहां व्यापक श्रम स्थानांतरण कार्यक्रम के तहत तिब्बती किसानों, चरवाहों और अन्य ग्रामीण श्रमिकों को अकुशल और कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

चीनी सरकार तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और उनके बौद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करती है।

तिब्बती अक्सर चीनी अधिकारियों द्वारा भेदभाव और मानवाधिकारों के हनन की शिकायत करते हैं और उनका आरोप है कि चीनी नीतियों का उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को मिटा देना है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने समाचार विज्ञप्ति में कहा, 'तिब्बतियों को आजीविका के दीर्घकालिक साधनों से दूर किया जा रहा है, जिसमें उनके परंपरागत रूप से ऊन और डेयरी उत्पादन जैसे रोजगार हुआ करते थे। इसकी जगह तुलनात्मक रूप से कम लाभ और कम वेतन वाले विनिर्माण और निर्माण जैसे अकुशल काम में लगाया जा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि तिब्बतियों को प्रशिक्षण केंद्रों से सीधे नए कार्यस्थलों पर स्थानांतरित किया जाता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ऐसी नौकरियों के लिए सहमति दी है या नहीं। विशेषज्ञों ने कहा कि लेकिन निगरानी न होने की वजह से यह सुनिश्चित करना असंभव हो जाता है कि क्या जो काम करवाया जा रहा है वह जबरन है या नहीं।

ओबोकाटा और अन्य लोगों ने चिंता जताई है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे 'नस्लीय भेदभाव की रोकथाम करनेवाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन' कर एक गैर-विविधता वाला, एक नस्लीय और एक जातीय राष्ट्र को बढ़ावा दिया जा सके।

उन्होंने चीन से तिब्बतियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रम स्थानांतरण कार्यक्रमों से बाहर निकलने के लिए किए गए उपायों के बारे में विवरण प्रदान करने, अपने नए रोजगार के स्थानों में तिब्बतियों की कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी करने और तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से झिंझियांग में मुस्लिम- उग्युर अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए चीनी सरकार को एक पत्र भी सौंपा।

ओबोकटा ने कहा, 'हम इन मामले में समानता देख रहे हैं, इसलिए हम इस समय तिब्बती लोगों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

◆ जी- ७ के नेता तिब्बत में मानवाधिकार और जबरन श्रम को लेकर चिंतित

savetibet.org/२२ मई, २०२३

सात राष्ट्रों के समूह के नेताओं का कहना है कि तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति 'हमारे लिए प्रमुख चिंता' है और वे इसके बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना जारी रखेंगे।

समूह के हाल ही में संपन्न वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक विज्ञप्ति में जी- ७ नेताओं ने कहा कि, 'हम तिब्बत और झिंझियांग सहित चीन में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते रहेंगे, जहां जबरन श्रम कार्यक्रम हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय है।'

तिब्बत के लिए मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले एक समूह- इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत- ने कहा, 'जी-७ नेताओं की यह विज्ञप्ति दर्शाती है कि तिब्बत में चीन के दुर्व्यवहार इस धरती पर कुछ सबसे प्रभावशाली नेताओं की नजरों से ओझल नहीं हैं।'

'तिब्बतियों पर अपने दमन को छिपाने की कोशिश करने या विदेशी सरकारों की आलोचनाओं का खंडन करने के बजाय बीजिंग में सरकार को बातचीत की मेज पर वापस आना चाहिए और दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती नेतृत्व की पहल का सकारात्मक जवाब देना चाहिए, ताकि लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत-चीन संघर्ष का शांतिपूर्वक समाधान किया जा सके।'

जी- ७ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होते हैं।

जी- ७ नेताओं ने हिरोशिमा में १९-२१ मई तक अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बैठक की।

तिब्बत में मानवाधिकार हनन

चीन ने ६० से अधिक वर्षों से तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस कारण दलाई लामा को १९५९ में निर्वासन में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

वाचडॉग ग्रुप 'फ्रीडम हाउस' की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, आज चीनी शासन के तहत तिब्बत दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ पृथ्वी पर सबसे कम आजाद देश है।

हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में पिछले साल तिब्बत में भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम नागरिकों को भी केवल धार्मिक आधार पर बिना सुनवाई के जबरन लापता होने, गिरफ्तारी, शारीरिक शोषण और लंबे समय तक हिरासत में रखने के आरोपों का जिक्र किया गया है।

इसके अलावा, चीनी सरकार ने कथित तौर पर लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों में भेज दिया है। वहां पर उन्हें चीनी संस्कृति में ढालने का उपक्रम किया जाता है और पाठ्यक्रम में मंदारिन लिपि वाली चीनी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जाता है।

२००९ के बाद से लगभग १६० तिब्बतियों ने अपने लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तिब्बत और चीन में आत्मदाह कर लिया है।

जबरन मजदूरी

तिब्बत में चीन के शासन का एक और परेशान करने वाला पहलू तिब्बतियों से कथित तौर पर जबरन श्रम करवाना है।

रिपोर्टों के अनुसार, २०१५ के बाद से कथित 'स्वैच्छिक कार्यक्रम' के माध्यम से लाखों तिब्बतियों को अपने पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली को छोड़ने और अकुशल श्रमिकों के तौर पर कम-वेतन वाली नौकरी के लिए मजबूर किया गया है।

२०२० में स्कॉलर एड्रियन ज़ेनज़ ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कार्यक्रम तिब्बत के लगभग आधे हिस्से में चलाया जा रहा है। इसमें २०२० के शुरुआती सात महीने में ही पांच लाख से अधिक ग्रामीण तिब्बतियों को उनकी भूमि से बेदखल कर सैन्य-शैली के प्रशिक्षण केंद्रों में धकेल दिया गया है।

अभी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के छह स्वतंत्र स्पेशल रिपोर्टियरों ने एक बयान जारी कर चिंता व्यक्त की कि तिब्बत में चीन के कथित 'श्रमिक स्थानांतरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का इस्तेमाल तिब्बत के धर्म, भाषा और संस्कृति को कमजोर करने और तिब्बतियों की निगरानी करने और उन्हें राजनीतिक रूप से स्वामिभक्त बनाने' के लिए किया जा रहा है।'

विशेषज्ञों ने चीनी सरकार से जबरन श्रम और तस्करी को रोकने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या करने और ऐसे कार्यक्रमों से पीड़ित हुए लोगों के लिए उपचार और मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

तिब्बत समस्या का समाधान

जी-७ देशों ने हाल के वर्षों में तिब्बतियों का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। २०२२ में जर्मनी में आयोजित शिखर सम्मेलन में जी-७ नेताओं ने कहा, 'हम चीन में मानवाधिकारों की गिरती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। हम चीन से सार्वभौमिक मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। इसके तहत हम मुख्य रूप से तिब्बत और झिंझियांग में जबरन श्रम कार्यक्रम को लेकर चिंतित है।

इसी तरह जी-७ के विदेश मंत्रियों ने भी २०२२ में कहा था, 'हम चीन, खासकर झिंझियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति से बहुत चिंतित हैं।' उन्होंने कहा, 'हम चीनी अधिकारियों से स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को झिंझियांग और तिब्बत में तत्काल सार्थक और निर्बाध रूप से जाने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त की संभावित यात्रा भी शामिल है।'

फरवरी २०२३ में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन- दोनों दलों ने 'रिसॉल्यूशन टू द तिब्बत-चाइना कंफ्लीक्ट (तिब्बत-चीन संघर्ष समाधान अधिनियम)' नामक प्रस्ताव को फिर से पारित कराने की प्रक्रिया शुरू किया है। यह एक ऐसा विधेयक है, जो चीन

के प्रतिनिधियों और दलाई लामा के दूतों के बीच बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए चीन पर दबाव डालेगा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी जो २०१० से ठप पड़ी हुई है।

द्विदलीय कानून में यह सुनिश्चित किया जाना है कि तिब्बतियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है और तिब्बत की कानूनी स्थिति अभी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निर्धारित की जानी है।

◆ कालोन नोरज़िन डोल्मा ने दक्षिणी भारत की यात्रा में तिब्बत में मानवाधिकारों के गिरती स्थिति पर चिंता जताई और कर्नाटक के तिब्बत समर्थक समूहों से मुलाकात की

tibet.net/१९ मई, २०२३

बेंगलुरु। सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग- के कालोन (मंत्री) नोरज़िन डोल्मा को तिब्बत, सीटीए और अन्य मामलों को लेकर एक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। गुरुवार, १८ मई को बेंगलुरु में आयोजित इस संगोष्ठी में २५० से अधिक छात्रों और आरवी इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के ५० कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

संगोष्ठी का सह आयोजन आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के मानवाधिकार प्रकोष्ठ और श्री निरंजन यू के नेतृत्व में भारत- तिब्बत मैत्री संघ द्वारा किया गया था।

कर्नाटक सरकार के वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस (सेवानिवृत्त) मदभुशी मदन गोपाल और कानून संस्थान के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) अंजिना रेड्डी केआर आरवी उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे।

संगोष्ठी के बाद कालोन नोरज़िन डोल्मा के नेतृत्व में सीटीए प्रतिनिधिमंडल ने लेफ्टिनेंट निजलिंगप्पा के भतीजे और निजलिंगप्पा नेशनल फाउंडेशन के सचिव श्री एसजी मंजूनाथ के साथ-साथ पूर्व सांसद, निजलिंगप्पा मेमोरियल ट्रस्ट, चित्रदुर्ग के सचिव श्री एच. हनुमानथप्पा और कर्नाटक सरकार के पीडब्ल्यूडी के सचिव डॉ क़े एस़ रेड्डी से मुलाकात की।

बाद में शाम को एचएसआर लेआउट, कालोन और सीटीए प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस डॉ मदन गोपाल कृष्ण और कनार्टक सरकार के पूर्व मुख्य प्रधान वन संरक्षक (भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी) श्री किशन सिंह सुगरा से मुलाकात की।

बेंगलुरु / २० मई २०२३। सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के कलोन (मंत्री) नोरज़िन डोल्मा ने १९ मई २०२३ को बेंगलुरु स्थित विश्वेश्वरपुरा कॉलेज ऑफ लॉ के संकाय सदस्यों और छात्रों को मुख्य अतिथि के तौर पर 'मानवाधिकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन' विषयक सेमिनार में संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईक्युएसी) द्वारा बेंगलुरु और मैसूर स्थित भारत- तिब्बत मैत्री संघ (आईएफटीएस) के सहयोग से श्री निरंजन यू के नेतृत्व में किया गया था।

संगोष्ठी की अध्यक्षता लॉ कॉलेज के शासी परिषद के अध्यक्ष श्री बी़ एऩ लोकेश ने की और इसमें प्रिंसिपल डॉ सुधा जी, आईक्यूएएस समन्वयक डॉ संजीव के गौड़ा जी़ एस़ , समन्वयक विश्वप्रिया सी़ , संकाय सदस्यों और छात्रों ने हिस्सा लिया।

अपने मुख्य भाषण में कालोन नोरज़िन डोल्मा ने तिब्बत के भीतर विकट स्थितियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को मिटा देने के उद्देश्य से व्यवस्थित और दमनकारी नीतियों के क्रियान्वयन से श्रोताओं को अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की मध्यम मार्ग दृष्टिकोण की नीति के बारे में भी बात की, जिसे परम पावन दलाई लामा ने लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने के लिए दोनों पक्षों के लाभ की अवधारणा से परिकल्पित किया था।

संगोष्ठी को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। अंत में दक्षिण क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे छुल्त्रिम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और कॉलेज के प्रशासकों के बीच सम्मान के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह का आदान-प्रदान भी किया गया।

२१ मई, २०२३, मैसूर। मैसूर में आधिकारिक तय कार्यक्रमों के तहत सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के कालोन (मंत्री) नोरज़िन डोल्मा ने दो शैक्षणिक संस्थानों- 'एसबीआरआर महाजन लॉ कॉलेज' और 'विद्यावर्द्धक लॉ कॉलेज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इट्स रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस' का दौरा किया और उन्हें संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस), मैसूरु के साथ रणनीति बैठक की और २० मई २०२३ को मैसूर में द शेनफेन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण पहल- तिब्बती सामुदायिक केंद्र (एमटीसीसी)- का दौरा किया।

सुबह कालोन ने सम्मानित अतिथि के रूप में एसबीआरआर महाजन लॉ कॉलेज के संकाय सदस्यों और छात्रों को राज्य स्तरीय संगोष्ठी में 'मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका' विषय पर संबोधित किया। इसमें मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ. सी. बसवराजू ने भी अपने विचार रखे।

संगोष्ठी की अध्यक्षता महाजन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री टी. मुरलीधर भागवत ने की। संगोष्ठी में महाजन एजुकेशन सोसाइटी की सचिव डॉ. टी. विजयलक्ष्मी मुरलीधर, पूजा भागवत महाजन पीजी सेंटर के निदेशक डॉ. सी.के. रेणुकार्य और एसबीआरआर महाजन लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रभुस्वामी एम.एम. के अलावा संकाय सदस्यों और कानून के छात्रों ने भाग लिया।

अपने संबोधन में कालोन ने १९५० में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे, तिब्बत के अंदर की स्थिति, औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों के जबरन नामांकन और डीएनए नमूनों के संग्रह पर प्रकाश डाला। उन्होंने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए सीटीए के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण की भी व्याख्या की।

दोपहर में कालोन नोरज़िन डोल्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में 'मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका' विषयक संगोष्ठी में अपना मुख्य भाषण दिया। इसमें उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और परम पावन १४वें दलाई लामा द्वारा कल्पित और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा अंगीकार की गई मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से चर्चा की।

विद्यावर्धन लॉ कॉलेज के अध्यक्ष श्री गुंडप्पा गौड़ा ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। संगोष्ठी में कॉलेज के सचिव श्री विश्वनाथ, कोषाध्यक्ष श्री श्रीशैल रामनवर, निदेशक प्रो.के.बी. वासुदेव, प्राचार्य डॉ. दीपू पी. और समन्वयक डॉ. बोरेगौड़ा सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

महाविद्यालय के श्री पी.एम. चिक्काबोरैया सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में कॉलेज के संकाय सदस्यों और छात्रों समेत करीब ३०० लोगों ने शिरकत की।

दोनों आयोजनों में दक्षिण क्षेत्र में सीटीए के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी जिग्मे सुल्त्रिम ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दोनों कॉलेजों में अपने संबोधन के बाद कालोन नोरज़िन डोल्मा ने आईटीएफएस मैसूरु टीम, संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ तिब्बत एडवोकेसी रणनीतियों को मजबूत करने के संबंध में एक संवादापरक चर्चा की।

इसके अलावा कालोन ने कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक और एमटीसीसी के अध्यक्ष श्री जे.पी. उर्स से मुलाकात की। एमटीसीसी की स्थापना शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करके स्थानीय तिब्बती समुदाय की सेवा करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी।

ये सभी कार्यक्रम आईटीएफएस द्वारा संबंधित कॉलेजों के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

इस बार की मैसूर यात्रा में कालोन के साथ दक्षिण क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी जिग्मे सुल्ट्रिम, लुगसुम तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी गुरु न्यिमा, दिक्यी लार्सो तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी चेमी दोरजी, हुनसूर तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी तेनजिंग धदोन, भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के ताशी दिकी और सीआरओ स्टाफ के सदस्य बने रहे।

◆ तिब्बत समर्थक मधु लिमये का जन्म शताब्दी समारोह और डॉ. निर्मला देशपांडे का स्मृति समारोह दिल्ली में आयोजित

tibet.net, ०१ मई २०२३

३० अप्रैल २०२३, नई दिल्ली। विख्यात समाजवादी चिंतकों में से एक उत्कृष्ट सांसद और तिब्बत के मित्र मधु लिमये का जन्म शताब्दी समारोह

३० अप्रैल २०२३ को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

इस शताब्दी समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रख्यात सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, समाजवादी कार्यकर्ताओं, मधु लिमये के मित्रों और आम जनता ने भाग लिया।

समारोह में भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), मजनूं का टीला और बौद्ध विहार के समयेलिंग तिब्बती बस्ती के तिब्बती प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

समारोह के आयोजकों में से एक भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार ने समारोह में सदस्यों को संबोधित किया। वरिष्ठ समाजवादी कार्यकर्ताओं और मधु लिमये के दोस्तों को समारोह में सम्मानित भी किया गया।

उसी दिन उत्साही तिब्बत समर्थक, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सांसद पद्म विभूषण डॉ. निर्मला देशपांडे का १५वां स्मृति दिवस कार्यक्रम नई दिल्ली के एमपी क्लब में मनाया गया।

इस अवसर पर आईटीसीओ और मजनूं का टीला और बौद्ध विहार के समयेलिंग तिब्बती बस्ती के तिब्बती प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और सदस्यों ने डॉ. निर्मला देशपांडे के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सामाजिक कार्य, शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य के क्षेत्र की ७ अग्रणी महिलाओं को डॉ. निर्मला देशपांडे स्मृति नारी सम्मान- २०२३ से सम्मानित किया गया। इनमें सीटीए के सुरक्षा विभाग की कलोन ग्यारी डोलमा भी थीं।

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. निर्मला देशपांडे द्वारा स्थापित गांधीवादी संगठनों के वैश्विक महासंघ अखिल भारत रचनात्मक समाज ने किया।

मधु लिमये और डॉ. निर्मला देशपांडे का संक्षिप्त परिचय

मधु लिमये (०१ मई १९२२ - ०८ जनवरी १९९५) एक प्रसिद्ध समाजवादी महापुरुष थे, जिन्होंने १९४० से लेकर अपने शानदार जीवन के अंत तक ५० से अधिक वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में योगदान दिया। वह राम मनोहर लोहिया के अनुयायी और तिब्बत के मित्र और उत्साही तिब्बत समर्थक जॉर्ज फर्नांडीस के साथी थे। वह १९६३, '६७, '७४ और '७७ में बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए एक उत्कृष्ट सांसद थे। वह एक अनुकरणीय समाजवादी थे जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साहस का परिचय दिया।

निर्मला देशपांडे (१७ अक्तूबर १९२९ - ०१ मई २००८) एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थीं जिन्होंने गांधीवादी विचार और दर्शन को अपनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और महिलाओं, आदिवासियों और भारत में वंचितों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह अगस्त १९९७ से अगस्त १९९९ तक और २४ जून २००४ से २०१० तक दो बार राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्हें २००६ में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ०१ मई २००८ को तड़के नई दिल्ली में ७९ वर्ष की आयु में उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई।

◆ भारत-तिब्बत मैत्री संघ ने चीन-तिब्बत संघर्ष समाधान के आह्वान को दोहराया

tibet.net / २२ मई २०२३

नई दिल्ली। भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस), बिहार और श्री कृष्ण जुबली लॉ (एसकेजे) कॉलेज, मुजफ्फरपुर ने तिब्बत की

संप्रभुता और तिब्बतियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर संयुक्त रूप से पिछले गुरुवार १८ मई को एक सेमिनार का आयोजन किया। भारत-तिब्बत मैत्री संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने आईटीएफएस की शुरुआत और इसके बैनर तले तिब्बत के मुद्दे के लिए जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, दीन दयाल उपाध्याय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, एस. निगलिंगप्पा, जॉर्ज फर्नांडिस और उनके जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने १९५९ में चीनी आक्रमण और तिब्बत पर चीनी कब्जे से पहले तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में वर्णित किया।

एसकेजे लॉ कॉलेज, मुजफ्फरपुर के निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि १९५०-५९ के बीच चीन द्वारा जबरन कब्जा किए जाने से पहले तक तिब्बत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न देश था। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने उस समय अपनी भूमिका निभाई होती तो चीन अपने गुप्त मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, 'यह केवल भारतीयों का ही नहीं बल्कि दुनिया के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह तिब्बतियों के साथ खड़ा रहे।'

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बीबीआरएयू विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कॉलेज इंस्पेक्टर और आईटीएफएस, बिहार की कार्यकारी समिति के सदस्य प्रोफेसर प्रमोद कुमार थे। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने तिब्बत के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने प्राचीन काल में तिब्बत को एक संप्रभु देश के रूप में वर्णित किया और तिब्बत की अपनी समृद्ध संस्कृति और दुनिया की छत और दक्षिण-पूर्व एशिया में पानी के स्रोत के रूप में तिब्बत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तिब्बत पर चीनी शासन, तिब्बत में नागरिक स्वतंत्रता के अभाव और तिब्बत में मानवाधिकारों के अभाव की आलोचना की।

एस.के.जे. लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. के.एन. तिवारी ने पीआरसी द्वारा तिब्बत में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों के उल्लंघन के बारे में बात की। उन्होंने यूएनओ और दुनिया की तथाकथित बड़ी शक्तियों की चुप्पी पर हैरानी जताई। उन्होंने तिब्बत के लिए मजबूत जनमत के निर्माण का आग्रह किया। उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने तिब्बत के बारे में विशेष रूप से बुद्धिजीवियों और सामान्य रूप से युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

एसकेजे लॉ कॉलेज के उप-प्राचार्य ब्रजमोहन कुमार आजाद ने अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तिब्बती मुद्दे के प्रणेता (स्वर्गीय) श्री राजनारायण राय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने में हर भारतीय की एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने भारत सरकार से चीन को तिब्बत के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करने के लिए तिब्बत के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने का अनुरोध किया।

डॉ. ब्रजेश कुमार शर्मा ने अपने भाषण में लोकसभाध्यक्ष और प्रधानमंत्री से परम पावन दलाई लामा को भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने परम पावन दलाई लामा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की भी अपील की।

◆ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने तिब्बती जन डीएनए संग्रह पर चिंता जताई

tibet.net, ११ मई २०२३

धर्मशाला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकेन ने बुधवार को तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह अभियान की खबरों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें पांच वर्ष तक के बच्चों सहित १२ लाख तिब्बतियों के डीएनए नमूने अब तक लिए गए हैं। इस सार्वजनिक चिंता को विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने फ्रीडम हाउस के वार्षिक फ्रीडम अवार्ड्स में उठाया था और इस चिंता को उजागर करने वाले वह अब तक के सबसे वरिष्ठ अमेरिकी प्राधिकारी बन गए है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, 'हम तिब्बती आबादी पर नियंत्रण और निगरानी की एक अतिरिक्त चीनी कवायद के तौर पर तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह के प्रसार की रिपोर्ट से काफी चिंतित हैं।'

तिब्बतियों को सामाजिक रूप से नियंत्रित करने के प्रयास में चीनी प्राधिकरण ने लगातार निगरानी और अति-पुलिसिंग का सहारा लिया है। इसमें तिब्बतियों से डीएनए नमूनों का मनमाना संग्रह भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा सितंबर- २०२२ में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएनए संग्रह के लिए रक्त के नमूने किंडरगार्टन में बच्चों और अन्य स्थानीय निवासियों से व्यवस्थित रूप से एकत्र किए जा रहे थे। दिसंबर- २०२० में किंघई प्रांत में एक तिब्बती टाउनशिप की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पांच वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लड़कों से डीएनए एकत्र किया जा रहा था।

इसने आगे कहा कि तिब्बती पठार के पश्चिमी भाग में अवस्थित टीएआर के सभी सात प्रिफेक्चरों या नगर पालिकाओं में इस तरह के सामूहिक डीएनए संग्रह अभियान चलाए गए। रिपोर्ट में खुलासा किए गए संग्रह अभियान चीनी अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र में जमीनी स्तर पर पुलिस निगरानी स्थापित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि रिपोर्ट उन परिस्थितियों के बारे में अस्पष्ट है कि डीएनए नमूना देने से इनकार करने वाले तिब्बतियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया।

एचआरडब्ल्यू की जांच के अनुसार, यह पाया गया कि अभियान को क्षेत्र के सात प्रीफेक्चर-स्तरीय क्षेत्रों में १४ अलग-अलग इलाकों (१ प्रीफेक्चर, २ काउंटी, २ कस्बों, २ टाउनशिप और ७ गांवों) में चलाया गया था, जो दर्शाता है कि अभियान पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं, या शुरू होने वाले हैं।

"डीएनए जानकारी अत्यधिक संवेदनशील है और बिना सहमति से इसे एकत्र या साझा किए जाने पर व्यापक पैमाने पर लोगों से दुर्व्यवहार किए जाने की आशंका पैदा हो जाती है। सरकार द्वारा कोई भी जबरन संग्रह या उपयोग निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी है। हालांकि चीनी सरकार द्वारा डीएनए संग्रह को कभी-कभी स्वीकार्य जांच उपकरण के रूप में उचित ठहराया जाता है, लेकिन निजता के अधिकार के साथ इस प्रकार के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। इस तरह के अभियान को छोटे दायरे में और केवल वैध सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही संतुलित आधार पर होना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'फिर भी चीनी सरकार के डेटा संग्रह अभियान में हर किसी से डीएनए जानकारी एकत्र की जा रही है। इस अभियान में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिनका डीएनए उेटा संग्रह किया जा रहा है वे किसी तरह से आपराधिक आरोप में हैं या नहीं। साथ ही डीएनए नमूने संग्रह किए जाने के दौरान न तो व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है और न ही उनकी सहमति ली जा रही है और कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।'

◆ दुर्दमनीय तिब्बत: करुणा और सच्चाई के बूते चीनी झूठ से लड़ने के सात दशक

(दशकों के क्रूर कम्युनिस्ट उत्पीड़न के बाद तिब्बत के लोग अविचलित और निडर हैं। परम पावन दलाई लामा उनकी विनम्रता के प्रेरणास्रोत हैं)

https://japan-forward.com / १९ मई, २०२३

जेसन मॉर्गन, रीटाकू विश्वविद्यालय

अक्सर यह कहा जाता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) एक अधिनायकवादी सरकार है। यह सच भी है। लेकिन बीजिंग के अधिनायकवादी तानाशाही को बर्दाश्त करने वाले लोगों के लिए ठोस रूप से इसका क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है और दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, तब एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महादेशों के अंतर्गत आने वाले देश क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसका उत्तर तिब्बत में पाया जा सकता है।

तिब्बत हमें सिखाता है कि चीनी अधिनायकवाद वास्तव में जमीन पर कैसा दिखता है। इसी तरह तिब्बत, विशेष रूप से आध्यात्मिक नेता परम पावन दलाई लामा क्रूर साम्यवादी उत्पीड़न के सामने आशा की एक किरण के रूप में दिखाई देते हैं और राह दिखाते हैं।

कम्युनिस्ट धर्म से नफरत करते हैं

यह सामान्य जानकारी है कि कम्युनिस्ट धर्म से घृणा करते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म को 'लोगों के अफीम' के रूप में बताया और उपहास उड़ाया था। स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने पादरियों और ननों को शिकार बनाया और चर्चों में तोड़फोड़ की। मेक्सिको में क्रिस्टरो युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। वियतनाम में कम्युनिस्टों ने पुजारियों और ननों का जनसंहार किया, गिरजाघर की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया और नियमित उपासना करने वालों को शिकार बनाया। यह पैटर्न हर उस जगह पर दोहराया गया है जहां कम्युनिस्टों ने सत्ता हथिया ली है। चाहे वह क्यूबा, उत्तर कोरिया, कंबोडिया, वेनेज़ुएला हो या पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। ये सब ऐसे अनेक उदाहरणों में से कुछ ही उदाहरण हैं।

हालांकि, कम्युनिस्ट धर्म से घृणा करते हैं, लेकिन अक्सर यह भी देखने में आया है कि वे इसके बिना शासन नहीं कर सकते। नास्तिक राज्य बनाने का कम्युनिस्टों का लक्ष्य असंभव प्रतीत होता है। जहाँ पारंपरिक धर्म की हत्या होती है, वहां नए पंथ बन जाते हैं।

शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण भूतपूर्व सोवियत संघ है, जिसने समझौता करने की कोशिश करने से पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। या माओत्से तुंग को देखें, जिसने जीवित देवता के रूप में पूजे जाने के दौरान चीन में जानलेवा अराजकता को बढ़ावा दिया।
कम्युनिस्ट धर्म से नफरत करते हैं। लेकिन, कम्युनिस्टों को भी यह अच्छी तरह से पता है कि धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। कई मामलों में यह उनकी नफरत को ही बढ़ाता है। इन परिस्थितियों में कम्युनिस्ट शासकों के हाथों धार्मिक नेताओं और आम लोगों को भयानक दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि नरसंहार भी झेलना पड़ता है।

धर्म-विरोधी घृणा के सात दशक

सत्तर साल से भी अधिक समय पहले तिब्बत में कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि चीन का नवनिर्मित पीपुल्स रिपब्लिक तिब्बत को 'मुक्त' कर देगा। उदाहरण के लिए दसवें पंचेन लामा चोएक्यी ग्यालत्सेन चीनी गृहयुद्ध में राष्ट्रवादियों के खिलाफ पीआरसी का पक्ष लेते दिखाई दिए।

हालांकि, कम्युनिस्ट शासन की वास्तविकता ने जल्द ही आदर्शवादी कल्पनाओं को मिटा दिया। १९५० में चीनी कम्युनिस्टों ने तिब्बत पर आक्रमण किया और बलपूर्वक देश पर कब्जा कर लिया। १९५१ में दलाई लामा को यह स्वीकार करते हुए 'समझौते' पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है। फिर १९५९ में अवलोकितेश्वर (करुणा के बोधिसत्व) के चौदहवें अवतार परम पावन दलाई लामा अपने गृह देश तिब्बत से भागकर पड़ोसी भारत आ गए।

तिब्बत की संस्कृति और लोगों का संहार

तिब्बत पर सात दशकों से अधिक के कम्युनिस्ट शासन के दौरान तिब्बती लोगों और उनके नेताओं को मानव जाति के इतिहास में शायद सबसे व्यापक, व्यवस्थित और लंबे समय तक चलने वाले नफरत और नरसंहार अभियान का शिकार होना पड़ा है। मठों और चैत्यों को जलाया गया है। बौद्ध भिक्षुओं को कैद करके मार दिया गया है। बौद्ध भिक्षुणियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। तिब्बत की समृद्ध बौद्ध विरासत को भौतिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। प्रार्थना चक्रों को अपवित्र और नष्ट कर दिया गया है। मूर्तियों को गिरा दिया गया है। सूत्र जलाए गए हैं।
गुप्त सीआईए गुरिल्ला कमांडो के रूप में तिब्बत में पैराशूट से उतर कर किए जाने वाले अमेरिकी हस्तक्षेप ने केवल चीजों को बदतर ही बनाया है।
दसवें पंचेन लामा ने एक बार कम्युनिस्टों का 'मुक्तिदाता' कहकर स्वागत किया था। लेकिन जब १९६२ में उन्होंने पीआरसी द्वारा तिब्बत में किए जा रहे बर्बर कार्रवाईयो के बारे में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एन लाई को अवगत कराने का साहस किया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था। १९८९ में दसवें पंचेन लामा मर चुके थे, संभवतः बीजिंग द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी।

इसके अलावा, एक छोटे लड़के ग्यारहवें पंचेन लामा का १९९५ में बीजिंग द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। पीआरसी ने तिब्बती लोगों पर एक नकली पंचेन लामा थोपा है। लेकिन बंदूक की नोक पर नकली लामा की पूजा करने के लिए मजबूर किए जाने के बावजूद तिब्बतियों ने ऐसे उपायों को लगभग सार्वभौमिक रूप से खारिज कर दिया है।

बीजिंग द्वारा तिब्बत की संस्कृति और वहां के नागरिकों के संहार के बीच पीआरसी की क्रूरता के विरोध में भिक्षुओं, भिक्षुणियों और अन्य आम तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह किया जाना जारी है।

तूफान आने से पहले की शांति

बीजिंग के अधिनायकवाद के तहत तिब्बती लोग सत्तर से अधिक वर्षों से पीड़ित हैं। उन्हें, उनके धर्म और उनकी संस्कृति को चीनी कम्युनिस्टों द्वारा समाप्त कर दिए जाने की योजना है।
इनमें से अधिकांश बर्बरता बेशक तिब्बत के अंदर चल रही है। यह चीनी सेंसरशिप द्वारा छिपाई गई है और इसे बाकी दुनिया की नज़रों से ओझल कर रखा गया है। हालांकि, परम पावन चौदहवें दलाई लामा निर्वासित तिब्बती सरकार के बीच भारत के धर्मशाला में रहते हैं। भारत में दलाई लामा का सार्वजनिक जीवन दुनिया को उस नफरती अभियान को देखने में मदद करता है जो पीआरसी ने उनके खिलाफ छेड़ रखा है।
बीजिंग नियमित रूप से दलाई लामा पर 'राष्ट्रतोड़क' और 'अलगाववादी'

होने का आरोप लगाता रहता है। एक चीनी अधिकारी ने दलाई लामा को 'भिक्षु के वेश में भेड़िया' और 'मानव चेहरे वाला राक्षस' कहा।

दलाई लामा से मिलने पर धमकी

बीजिंग नियमित रूप से लोगों और सरकारों को परम पावन दलाई लामा से संवाद करने या उनसे मिलने के खिलाफ धमकी भी देता रहता है। वाशिंगटन, श्रीलंका, भारत, फ्रांस, मंगोलिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ और यहां तक कि लेडी गागा को परम पावन से मिलने के लिए चीन द्वारा फटकार लगाई गई और सीधे तौर पर धमकी दी गई।

सीसीपी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट में कार्यकारी उप मंत्री झांग यिजोंग ने कहा कि वास्तव में, चीनी सरकार स्वीकार करती है कि वह दलाई लामा के साथ बातचीत करने वालों को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। जैसा कि इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, 'किसी भी देश या किसी के किसी संगठन का दलाई लामा से मिलना हमारे विचार में चीनी लोगों की भावनाओं के प्रति एक बड़ा अपराध होगा।'

स्वयं दलाई लामा को भी यूरोपीय संघ यात्रा की यात्रा करने पर धमकी दी गई थी। २०१२ में, दलाई लामा ने अपनी हत्या करने की चीनी योजनाओं का भी खुलासा किया।

आधिकारिक तौर पर नास्तिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म में दखल देने के अधिकार का बेतुका दावा कर रही है। यहां तक कि चीनी कम्युनिस्टों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म और उसमें दलाई लामा के स्थान के बारे में झूठ फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भी बेशर्मी से इस्तेमाल किया गया है।

तिब्बतियों से अधिनायकवादी चीन की ताजा नफरत

अप्रैल २०२३ में चीन ने शातिराना तरीके से परम पावन दलाई लामा को फर्जी खबरों में फंसाने की विशेष रूप से कोशिश की थी। चीनी अफवाहों में आरोप लगाया गया था कि उत्तर भारत में एक कार्यक्रम के दौरान दलाई लामा ने एक किशोर के साथ अत्यधिक अनुचित व्यवहार किया।

हालांकि, भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग या राष्ट्रपति पेन्पा छेरिंग ने समझाया कि परम पावन का व्यवहार 'निर्दोष' था। यह अनुचित नहीं था, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त 'स्नेह' का प्रदर्शन किया था।

तिब्बत हाउस जापान के प्रमुख और तिब्बती धर्म और इतिहास के विद्वान डॉ. छेवांग ग्यालपो आर्य लिखते हैं कि :

'अमेरिका में रहने वाले एक तिब्बती श्री जिग्मे उगेन ने वीडियो के पूरे फुटेज में दर्शाई गई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि दलाई लामा द्वारा बच्चे के साथ मासूमियत भरे व्यवहार को सनसनीखेज बनाने में चीन के छिपे हुए हाथ थे। बाद में यह परम पावन दलाई लामा को बदनाम करने और मातृभूमि में स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनके तिब्बती संघर्ष को कमजोर करने के एक और चीनी साजिश के रूप में सामने आया।

नीचतापूर्ण चाल

कहानी में और भी बहुत कुछ है। डॉ. आर्य आगे बताते है:

'सीसीपी द्वारा चले गए इस घृणित चाल का एक और कारण यह था कि ०८ मार्च को परम पावन ने भारत के धर्मशाला में एक धार्मिक समारोह में एक लड़के को १०वें जेटसन धम्पा हुथुक्थु (जेबत्सुंदम्बा) के रूप में मान्यता दी, जो उच्चतम मंगोलियाई बौद्ध लामाओं में से एक हैं। ६०० मंगोलियाई और कई तिब्बतियों ने पवित्र समारोह में भाग लिया। मंगोलों और तिब्बतियों के बीच एक गहरा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। असल में, नौवें जेटसन धम्पा हुथुक्थु चीन से भाग गए और तिब्बतियों के साथ भारत में शरण मांगी।'

अप्रैल २०२३ में दलाई लामा पर चीन द्वारा फर्जी अफवाही खबरों से हमले में और तेजी से और बहुत पुराने फर्जी समाचारों में शामिल किया गया। चीनियों ने किशोर से दलाई लामा की बातचीत को गलत तरीके से उड़ाते हुए झूठ फैलाया कि दलाई लामा ने कहा कि कि चीन के तिब्बत मे आने से पहले तिब्बती 'गुलाम' थे।

चीन के अधिनायकवाद से आगे भी राह है

यह स्पष्ट है कि बीजिंग दलाई लामा से नफरत क्यों करता है। असल में दलाई लामा एक आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था और उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे पूरी मानव जाति स्वीकार करती है। तिब्बत, मंगोलिया, शेष एशिया, पश्चिम, और यहां तक कि चीन के लोग भी तिब्बती बौद्ध धर्म की सराहना करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग दलाई लामा का सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं और उनकी तरह करुणा और सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं।

जापान में भी, सांसदों का एक समूह तिब्बत के समर्थन में एक साथ आने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम कर रहा है। दलाई लामा का काशीवा, जापान में रीताकू विश्वविद्यालय में स्वागत किया गया है और इसी तरह सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का भी स्वागत किया गया है।

चीन जहां दमन करता है, नष्ट करता है, मारता है और धमकाता है, वहीं दलाई लामा करुणा और प्रेम बिखेरते हैं। दलाई लामा ने बीजिंग की नफरत का कभी भी किसी तरह से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, परम पावन दलाई लामा सुलह, शांति और आनंद की बात करते हैं। उन्होंने तिब्बत और चीन के बीच सह-अस्तित्व के लिए शायद अपने आध्यात्मिक पूर्वज चोंखापा की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करते हुए 'मध्यम मार्ग' का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है।

अधिनायकवादी तानाशाही के लगभग तीन-चौथाई सदी के बाद भी तिब्बती लोग अविचलित और निडर बने हुए हैं। दलाई लामा उनकी इस विनम्रता के प्रेरणास्रोत हैं।

और इससे भी आगे की बात है कि परम पावन केवल तिब्बतियों के लिए नहीं हैं। दुनिया में कोई भी दलाई लामा को देख सकता है और जान सकता है कि कम्युनिस्ट तानाशाही धर्म के खिलाफ शक्तिहीन है। अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है।

◆ स्विस पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह पर थर्मो फिशर को खुला पत्र भेजा

tibet.net, २५ मई २०२३

जिनेवा। स्विस पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत ने चीन में अनैतिक क्रियाकलापों, विशेष रूप से तिब्बत में तिब्बतियों के सामूहिक डीएनए संग्रह के बारे में मिली जानकारी को लेकर गहरी चिंता प्रकट की है और थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. से इस बारे में 'संदेह दूर करने' की अपील की है।

थर्मो फिशर साइंटिफिक के अध्यक्ष को संबोधित एक खुले पत्र में पार्लियामेंटरी ग्रुप ने अपनी इन चिंताओं को व्यक्त किया कि कंपनी संभवत: तिब्बत में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर दमनकारी नीतियों और क्रियाकलापों का 'समर्थन' कर रही है। संसदीय समूह ने कंपनी से तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह के लिए चीन को सामग्री की आपूर्ति करते समय समुचित तरीके से परिश्रम करने के साथ कार्य व्यापार के लिए अपनाए गए मानदंडों का खुलासा करने की भी अपील की है।

समूह ने थर्मो फिशर से उन मानदंडों का खुलासा करने की अपील की है जो चीन को 'उपलब्ध कराई गई सामग्री के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करता है। कंपनी से चीन द्वारा नमूना संग्रह और डेटा के विश्लेषण के नैतिक उपयोग की 'गारंटी' की मांग की गई है। गौरतलब है कि संसदीय समूह ने चीन को डीएनए नमूना संग्रह उपकरण की आपूर्ति के संबंध में थर्मो फिशर द्वारा 'हेलसिंकी घोषणा' के अनुपालन का मुद्दा उठाया था। शोध रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी अधिकारियों द्वारा 'सामूहिक स्वास्थ्य जांच' सहित विभिन्न कार्यक्रमों के बहाने पांच साल और इससे अधिक उम्र के लगभग दस लाख तिब्बतियों से बड़े पैमाने पर डीएनए नमूना संग्रह किया जा रहा है।

स्विस पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के साथ ०७ मार्च २०२३ को आयोजित पिछली बैठक के दौरान चीन द्वारा तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह पर विस्तार से चर्चा की गई थी और सांसदों से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। बैठक के दौरान संसदीय समूह के सदस्यों द्वारा कहा गया कि संसदीय समूह तिब्बत में स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तिब्बत और चीन में अनैतिक क्रियाकलापों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने स्विस पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के रुख का स्वागत किया और चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

◆ संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय ने चीन से तिब्बती महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया

tibet.net, ३१ मई २०२३

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय के हाल ही में समाप्त हुए ८५वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यु)- ने चीन से तिब्बत में भेदभाव और बाधाओं का सामना कर रहीं तिब्बती महिलाएं समेत सभी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय द्वारा समीक्षा की स्थापित कार्यवाही के अनुसार सीईडीएडब्ल्यू का सत्र ०८ मई को शुरू हुआ और २६ मई २०२३ को समाप्त हुआ। इस दौरान १२ मई २०२३ को समिति द्वारा चीन की नौवीं आवधिक रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

३० मई २०२३ को प्रकाशित समिति की समापन अवलोकन रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र समिति ने तिब्बत में तिब्बती महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कई तरह की चिंताएं उठाईं, जिनमें न्याय मिलने में बाधाएं, स्कूल बंदी, अनिवार्य आवासीय विद्यालय, तिब्बती भाषा में शिक्षा से इनकार, पासपोर्ट की जब्ती, जबरन मजदूरी और जबरन विवाह, तिब्बती महिलाओं की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कमतर करके आंकना शामिल हैं।

श्रमिकों के जबरन स्थानांतरण और तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर समिति 'चिंतित रहती है', जिसके तहत तिब्बती महिलाओं को उनके अद्वितीय कौशल से हटाकर कम-कुशल कार्यों के लिए प्रशिक्षित होने के लिए मजबूर किया जाता है। समिति ने इस बारे में चिंता जताते हुए चीन से तिब्बत में अनिइक्छुक श्रमिकों के स्थांतरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तुरंत रोकने और प्रभावित तिब्बती महिलाओं के साथ सार्थक परामर्श करने का आह्वान किया। इसके अलावा, समिति ने चीन से तिब्बती महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान, संरक्षण और प्रचार करने और तिब्बती महिलाओं सहित जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के 'अन्तर्विभाजक' रूपों को खत्म करने का आग्रह किया।

तिब्बत में स्कूलों को जबरन बंद करने और आवासीय स्कूलों में अनिवार्य रूप से दाखिला दिलाने की खबरों पर प्रकाश डालते हुए समिति ने चीन से तिब्बती लड़कियों पर थोपी गई आवासीय स्कूल प्रणाली को खत्म करने और निजी तिब्बती स्कूलों की स्थापना और सब्सिडी देकर तिब्बती भाषा में शिक्षा देने का आह्वान किया। इसके अलावा, तिब्बतियों से पासपोर्ट जब्त करने की रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए समिति ने चीन को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की कि नस्लीय रूप से अल्पसंख्यक तिब्बतियों के पासपोर्ट जब्त नहीं किए जाएं और पासपोर्ट को जब्त करने में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मनमाने ढंग से उपयोग न किया जाए। कई न्यायाधीशों द्वारा न्याय देने में लैंगिक पूर्वाग्रह पालने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र समिति ने तिब्बती महिलाओं सहित सभी वंचित महिला समूहों द्वारा न्याय पाने में आर्थिक और भाषाई बाधाओं का मुद्दा उठाया।

समिति की पिछली सिफारिश को दोहराते हुए चीन को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की एक व्यापक परिभाषा अपनाने के लिए कहा गया है, जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। समिति ने उचित प्रवर्तन तंत्र और प्रतिबंधों के माध्यम से तिब्बती महिलाओं

सहित सभी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के निषेध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चीन से आह्वान किया।

सीईडीएडब्ल्यु की समापन अवलोकन रिपोर्ट का स्वागत करते हुए प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने अपने जनादेश को बरकरार रखने के लिए समिति को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने कहा, 'तिब्बत पर समिति द्वारा चीनी सरकार को की गई मजबूत और ठोस टिप्पणियां और सिफारिशें चीन की भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रथाओं के तहत तिब्बती महिलाओं के सामने आने वाली गंभीर स्थिति और चुनौतियों को दर्शाती हैं। इसी तरह, समीक्षा को सफल और सार्थक बनाने के लिए चीन को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।'

तिब्बत ब्यूरो-जिनेवा, तिब्बतन वूमन एसोसिएशन-सेंट्रल और तिब्बत एडवोकेसी कोएलिशन सहित तिब्बत समूहों ने पूरी समीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया। तीनों समूहों ने अलग-अलग लिखित निवेदन किए और तिब्बत में तिब्बती महिलाओं की स्थिति के बारे में विशेषज्ञों को जानकारी भी दी।

◆ सीआरओ जिग्मे सुल्ट्रिम ने तिब्बती नेतृत्व की ओर से कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को बधाई पत्र भेजा

tibet.net, २३ मई २०२३

बेंगलुरु। दक्षिण क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी (सीआरओ) जिग्मे सुल्ट्रिम ने परम पावन दलाई लामा का बधाई पत्र माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दिया, जिन्होंने २२ मई २०२३ को कर्नाटक के २५वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

सीआरओ ने सिक्योंग पेन्पा छेरिंग और स्पीकर भिक्षु खेनपो सोनम तेनफेल का बधाई पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। क्रमशः पत्रों को पढ़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने पांच बस्तियों (कर्नाटक राज्य के तीन जिलों के चार तालुकों में) में निर्वासित तिब्बती समुदायों के लिए सुविधाओं की देखभाल में अपना अत्यधिक समर्थन देने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर सीआरओ ने राज्य में अपने लोगों के उत्थान और समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक उपलब्धियों की पहचान स्वरूप एक बुद्ध प्रतिमा भी भेंट की।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद से माननीय सिद्धारमैया को तिब्बती नेताओं के संदेशों के साथ-साथ कई अन्य लोगों से बधाई और शुभकामनाएं मिली हैं।

◆ धोंडुप वांगचेन ने परिवार के साथ टोक्यो की यात्रा की

tibet.net, २९ मई २०२३

टोक्यो। डर को पीछे छोड़ते हुए २००८ में वीरतापूर्ण फिल्म 'जिगद्राल' का निर्माण कर तिब्बत में चीनी क्रूर नीति का पर्दाफाश करने वाले बहादुर तिब्बती देशभक्त धोंडुप वांगचेन पिछले बुधवार को अपने परिवार के साथ टोक्यो गए थे। तिब्बत फिल्म्स एंड टॉक्स कमेटी (चिबेटो नो एइगा जोई टू टोक) ने टोक्यो और कई अन्य स्थानों पर धोंडुप वांगचेन की यात्रा और वार्ता का आयोजन किया।

जापान में आयोजकों और तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने २४ मई को टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर फिल्म निर्माता और उनके परिवार का स्वागत किया।

धोंडुप वांगचेन ने २६ मई को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब फॉर जापान (एफसीसीजे) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने २००८ की गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग की पृष्ठभूमि में तिब्बत की स्थिति और तिब्बती भाषा और संस्कृति का चीनीकरण करने की चीनी नीति की व्याख्या की। बाद में दोपहर में उन्होंने एक वीडियो स्क्रीनिंग में भाग लिया और मीजी विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया।

२७ मई को फिल्म निर्माता और उनके परिवार ने शिंजुकु हॉल में अपने संघर्ष और जीवन के अनुभवों के बारे में बात की। उनकी पत्नी ल्हामो छो और दो बेटियों धदोन और ल्हामो ने बताया कि कैसे वे अपने पिता की समय पर एक चीनी जेल से रिहाई और तिब्बत से उनके अंतिम पलायन और अमेरिका में शरण के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे।

परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ आर्य छेवांग ग्यालपो ने धोंडुप वांगचेन और तिब्बत में स्वतंत्रता और न्याय की दुर्लभता के खिलाफ उनके परिवार द्वारा किए गए संघर्षों का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने श्रोताओं को तिब्बत की स्थिति और सीसीपी नेतृत्व द्वारा तिब्बती धर्म, संस्कृति और भाषा को नष्ट करके तिब्बती पहचान को मिटाने की साजिशों के बारे में जानकारी दी।

धोंडुप वांगचेन और उनके परिवार को उनके योगदान और बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधि आर्य ने आयोजकों मैरी ओगावा, हिरोमी इकेदा और अन्य लोगों को जापान में धोंडुप वांगचेन की यात्रा और वार्ता को संभव बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

तिब्बत हाउस, जापान ने धोंडुप वांगचेन और उनके परिवार का आज २९ मई को कार्यालय में स्वागत किया, जहां प्रतिनिधि आर्य और कर्मचारियों ने परिवार की अगवानी की और उन्हें जापान की स्थिति और कार्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। तिब्बत हाउस ने तिब्बती मुद्दे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बाद में, तिब्बत हाउस जापान ने परिवार के लिए दोपहर के भोज का आयोजन किया। धोंडुप वांगचेन और उनके परिवार के साथ जापान में तिब्बती समुदाय के लोबसांग येशे भी थे।

टोक्यो के अलावा, आयोजकों ने नागोया, फुकुओका सिटी, ओसाका, कोच्चि और कामाकुरा में धोंडुप वांगचेन की फिल्म स्क्रीनिंग और वार्ता की योजना बनाई है। धोंडुप वांगचेन कल ३० मई से इन शहरों की यात्रा करेंगे। इन आयोजनों को एमनेस्टी इंटरनेशनल, सुपर संघ, एसएफटी जापान, पुफेस्ट तिब्बत कमेटी, तिब्बत हाउस,जापान आदि का समर्थन प्राप्त है।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीचे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com , coordinator@indiatibet.net

May, 2023, Years: 44 Issue: 05 Regd No. : RNI 34636-79

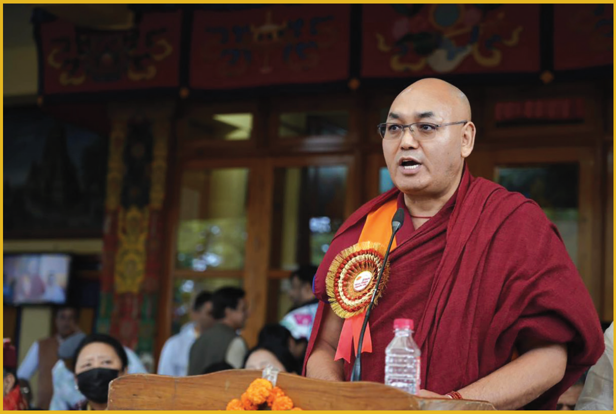

धर्मशाला में भारत तिब्बत सहयोग मंच की रजत जयंती समारोह।